Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

दैनिक

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 2 अंक: 204 , 30 दिसम्बर, शनिवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

एमसीडी कर्तव्यों के निर्वहन में कर रहा गंभीर लापरवाही : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके सामने आयी ढेरों याचिकाओं में राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत निर्माण के लगाये गये आरोपों का सही पाया जाना नगर निगमों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में भारी लापरवाही दर्शाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक पंजीकृत सोसायटी की याचिका र सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सोसायटी ने याचिका में पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों की ओर इशारा किया है। पीठ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को उसके अंतर्गत आने वाले अपने क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण कराने और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्वाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस संबंध में उसके द्वारा उठाये गये कदमों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले साल चार अप्रैल को होगी। दिल्ली नगर निगम अधिनयम, 1957 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना नगर निगमों की महती जिम्मेदारी है।

एक जनवरी से लाजपत नगर फ्लाईओवर की मरम्मत शुरू, बंद रहेगा मार्ग

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली यातायात पुलिस ने लाजपत नगर फ्लाईओवर पर पीडब्ल्यूडी द्वारा 1 जनवरी 2018 से शुरू किए जा रहे चरणबद्ध मरम्मती कार्य के दौरान मूलचंद से आश्रम चौक तक मार्ग बंद रहने की सूचना जारी की है। इस दौरान पहले चरण में 1 जनवरी से 14 जनवरी तक मार्ग बंद रहेगा। दूसरे चरण में 15 जनवरी से 28 जनवरी 2018 तक मरम्मती कार्य हेतु बंद रहेगा। पुलिस उपायुक्त विजय सिंह ने बताया कि उक्त फ्लाईओवर से होकर गुजरने वाले लोग मरम्मती कार्य के दौरान फ्लाईओवर के नीचे से होकर जाने वाली सड़क का इस्तेमाल कर सकेंगे। दक्षिणी दिल्ली से नई दिल्ली या मध्य दिल्ली की तरफ जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले, इस सड़क पर होने वाली जाम से बचने के लिए लोगों को मथूरा रोड, आश्रम चौक, रिंग रोड, मूलचंद फ्लाईओवर, लोधी रोड, भीष्म पितामह मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

कर लगाने की जगह भ्रष्टाचार पर लगे अंकुश

पूर्वी दिल्ली। स्थायी समिति की बैठक में निगमायुक्त डॉ. रणवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों पर चंचा शुरू करते हुए विपक्ष की तरफ से आप पार्षद रेखा त्यागी ने बजट को पूरी तरह कागजी व जमीनी हकीकत से अलग बताया। बजट में कहीं भी निगम को किसी तरह मजबूत किया जाए, ऐसी कोई नीति नजर नहीं आई है। यदि निगम की आय बढ़ानी है तो कर लगाने की नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। निगम अपने पास मौजूदा संसाधनों को तो पूरी तरह से दोहन करने में असमर्थ और पल्ला झाड़ने के लिए आम जनता पर नए कर लगाने की बात कही जा रही है। वह निगम को चमकाने में रात-दिन एक करें, लेकिन यह भूल जाते हैं।

सटरिंग खोलने के दौरान हादसे में युवक की मौत

नई दिल्ली। थाना अमन विहार क्षेत्र के शनि बाजार रोड स्थित गौरवनगर-2, प्रेम नगर-3 में निर्माणधीन मकान की सटरिंग खोलने के दौरान जीने का लेंटर खोलते ही भरभराकर गिर पड़ा। इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त जनता एन्क्लेव प्रेमनगर-3 निवासी गुडडू ((28) पिता रामगोपाल के तौर पर हुई । पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 10 बजे के करीब की है, जहां 25 गज के निर्माणधीन मकान ए ब्लॉक गौरवनगर-2 प्रेमनगर-3 में काम चल रहा था। सटरिंग खोलने के दौरान जीने का लेंटर खोलते ही भरभराकर गिर गया।

प्राधिकरणों की नाकामी ने दिल्ली को एक प्रदूषित शहर बनाया : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के प्राधिकरणों की खिंचाई करते हुए कहा है कि यदि वे अपनी आंखें खुली रखते, तो राष्ट्रीय राजधानी एक प्रदूषित शहर नहीं बनता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने आवासीय और नन - कंफर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को इजाजत देने में नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत पर नाराजगी जाहिर की। पीठ ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को जांच करने और अदालत को उद्योगों का क्षेत्रवार ब्योरा अगले साल 19 फरवरी से पहले देने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में पानी की दरों में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता।

मेयर ने भी खायी अटल जनाहार केंद्र की थाली

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर कमलजीत सहरावत ने बृहस्पतिवार को ग्रीन पार्क में चल रहे अटल जन आहार केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाने की थाली के लिए लाइन में लगे लोगों सेखाने की गुणवत्ता को लेकर जानकारी भी ली। मेयर खुद भी 10 रपए देकर खाने की थाली का स्वाद चखा। मेयर ने दावा किया कि खाना खा रहे लोगों के खाने की गुणवत्ता को लेकर संतुष्टि जतायी है। मेयर ने वहां मौजूद गरीबों को कंबल एवं शॉल वितरित किये। इसके साथ ही गरीबों की मदद के लिए लोगों से भी मदद का आग्रह किया। इसके लिए जन आहार केंद्र के पास ही एक बॉक्स रखा गया है।

6-14 जनवरी तक प्रगति मैदान में चलेगा पुस्तक मेला

नए साल के पहले सप्ताह से शुरू होगा पुस्तक मेला

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए साल के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले पुस्तक मेले में इस बार करीब आठ हजार से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को डिस्प्ले करेंगे। प्रगति मैदान में लगने वाले इस पुस्तक मेले में इस बार पर्यावरण और स्वच्छता से जुड़ी ढेरो किताबें आ रही हैं। इसके अलावा डिजिटल फार्मेट में भी बड़ी संख्या में किताबें पुस्तक प्रेमियों के लिए होंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले इस पुस्तक मेले में विभिन्न भारतीय भाषाओं के बड़े प्रकाशक कई जाने-माने लेखकों की रचनाओं को लेकर आ रहे हैं। अलावा नए लेखकों की किताबें भी इस पुस्तक मेले में पाठकों को पढ़ने को मिलेगी। जानकारी के अनुसार पुस्तक मेले में कुछ फिल्मी दुनिया के कलाकार भी कुछ लेखकों की किताबों का लोकार्पण करने आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किताबों समेत पर्सनालिटी डवलपमेंट वाली किताबों पर सेमिनार भी आयोजित की जाएगी। प्रगति मैदान में पुर्ननिर्माण कार्य चलने की वजह से इस बार बुक फेयर का आयोजन हाल नम्बर सात से 12 और 12ए में किया जाएगा। पुस्तक प्रेमियों के लिए फेयर के दरवाजे सुबह 11 बजे से लेकर रात आठ बजे तक खुला रहेगा। फेयर में ज्यादा से ज्यादा पुस्तक प्रेमी आए इसके लिए जहां एक ओर आयोजकों की ओर से विशेष कोशिश की जा रही है वहीं दूसरी ओर हर प्रकाशक अपनी ओर से अपने पाठकों को प्रगति मैदान तक लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वाट्सअप से लेकर फेसबुक और ट्वीटर का सहारा लिया जा रहा है। लेखक और पाठकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए पुस्तक मेले में आर्थर कॉरनर होगा, जहां दोनों आपस में बातचीत कर सकेंगे।

पेयजल में बढ़ोतरी के विरोध में मुख्यमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन

"पानी माफ-बिजली हाफ' केजरीवाल का चुनावी वादा झूठा : गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी में पेजयल की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में बृहस्पतिवार को भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री आवास के पास हुए प्रदर्शन में गुप्ता ने केजरीवाल को याद दिलाया कि वह ''पानी माफ-बिजली हाफ' के चुनावी दावे पर सत्ता में आये थे, लेकिन उनकी सरकार तीन साल में दो बार पानी की दरें बढ़ा चुकी है। पार्टी के बड़े नेताओं में पवन शर्मा, राजीव बब्बर, राजेश भाटिया, अभय वर्मा समेत मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष भी थे।

नेता विपक्ष की अगुवाई में भाजपा नेता प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए और पैदल मार्च की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास की तरफ चल दिये, लेकिन पुलिस ने पहले से ही वहां बैरिकेड लगा रखे थे।

पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक दिया। विजेंद्र गुप्ता ने संबोधन में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सत्ता में जिस चुनावी वादे के साथ सत्ता में आये थे, आज उन्हें भुलाकर दिल्लीवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देने की योजना का लाभ किसी भी नियमित उपभोक्ता को नहीं मिला। केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिला, जिन्होंने मीटर नहीं ले रखा है। गुप्ता ने केजरीवाल के इस दावे को गलत बताया कि दिल्ली जल बोर्ड फायदे में हैं। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर प्रतिवर्ष 500 से 600 करोड़ रपए पड़ेगा।

पूर्व विधायक पवन शर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लाखों लोगों को निराश किया है। तीन साल में एक भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने की पहल तक शुरू नहीं की। उनके लिए मुफ्त पानी आज भी सपना है।

वर्तमान प्रस्ताव व ई-कॉमर्स के बीच एक गलत धारणा बनाई जा रही

मुद्दों को मीडिया व बयानबाजी से उलझाया जा रहा है : एलजी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकारी सेवाओं के सार्वजनिक वितरण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट मीडिया में आने पर एलजी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इसे गलत सूचना के आधार पर जानबूझ कर या अनजाने में अनदेखी करार दिया है। एक गलत धारणा के आधार पर यह फैलाया जा रहा है कि इस मामले में उपराज्यपाल के कार्यालय के कारण देरी हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि 18 दिसम्बर 2017 को इसे संबंधित पत्रावली मुख्यमंत्री द्वारा एलजी के कार्यालय में प्राप्त हुई। पत्रावली को 26 दिसम्बर को पुनर्विचार हेतु लौटा दी गई। इस संबंध में संबंधित विभाग ने पहले ही आगे बढ़कर निविदा जारी करने का काम शुरू कर दिया था। राजनिवास ने स्पष्ट किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परामर्श मार्ग लेने की और उद्देश्यपूर्ण सलाह पर विचार करने के बजाए इस मामले को मीडिया, बहस और बयानबाजी से हल करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी सेवा के मामले में राजनिवास ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार के वर्तमान प्रस्ताव और ई-कॉमर्स के बीच एक गलत धारणा बनाई जा रही है।

पिज्जा और अन्य अनेक ई-कामर्स उत्पादों को डाउनलोड करने की तकनीक अभी नहीं है। सरकार के प्रस्ताव में बहुत सी प्रस्तावित सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन दी जा रही हैं। इसके अलावा पीजा और अन्य ई-कॉमर्स उत्पाद की डिलिवरी को मोबाइल सहायकों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स के विपरीत जो व्यापार से उपभोक्ता का लेने-देन है सरकार को इसके लिए अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए और सरकार से उपभोक्ता लेन-देन के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिंता भी होनी चाहिए। मीडिया में यह खबर भी है कि अभी भी पहले से ही बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन हैं फिर भी कार्यालयों के बाहर कतारें लगी हुई हैं इसी कारण से उपराज्यपाल ने ऑनलाइन सेवा व्यवस्था के मध्य अंतराल का सुझाव दिया और बेरोजगार युवाओं द्वारा इंटरनेट कियोस्क स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने की सलाह भी दी। मीडिया में यह भ्रामक दावे भी हैं कि सेवाओं की होम डिलीवरी डिजिटल डिलीवरी को सुनिश्चित करेगी जहां पर 100 प्रतिशत डिजिटल डिलीवरी मॉडल का मतलब मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत का न होना है। डिलीवरी की प्रस्तावित पप्रणाली जिसमें हजारों मोबाइल सहायकों द्वारा जो सुविधा शुल्क एकत्र करेंगे वह व्यर्थ के अनावश्यक स्तर को आमंत्रित करेंगे।

रिश्वत लेता दिल्ली पुलिस का एसआई गिरफ्तार

नई दिल्ली। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक को एक व्यक्ति से 1.20 लाख रपए की कथित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति ने उसके (पुलिस उप निरीक्षक के) इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की थी। उस व्यक्ति ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में इलाके में कथित अवैध निर्माण के बारे में शिकायत की थी। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि अवैध निर्माण में कथित तौर पर शामिल लोगों ने शिकायतकर्ता पर शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाने के लिए इलाके के पुलिस उप निरीक्षक विजय कुमार से संपर्क किया। आरोप है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया, जब उसने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला ली। कुमार ने शिकायत करने वाले को कथित तौर पर धमकाया कि वह उसके खिलाफ जबरन धन उगाही का मामला दर्ज करेगा। उससे कहा गया कि वह उसपर जबरन उगाही के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने का आरोप लगाया जाएगा। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि कुमार ने उससे पांच लाख रपये की मांग की और उससे नगर निगम और पुलिस के पास से अपनी शिकायत वापस लेने को कहा। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौर ने बताया, शिकायतकर्ता के साथ सौदेबाजी के बाद उप निरीक्षक कथित तौर पर दो लाख रपये की रिश्वत लेने के लिये राजी हो गया। ऐसा आरोप है कि पुलिस उप निरीक्षक ने शिकायतकर्ता पर दिल्ली पुलिस से अपनी शिकायत वापस लेने का भी दबाव डाला। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कृष्णा नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद उसे शिकायतकर्ता से 1.20 लाख रपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

निर्माण भवन पर नसरे का डेरा, पुलिस ने उठाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेज में बर्खास्त किए गए संविदा नर्सिग कर्मचारियों का प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। बृहस्पतिवार को निर्माण भवन के बाहर नर्सों ने न सिर्फ डेरा जमा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की बल्कि निकाली गई नसरे को अविलंब बहाली की पुरजोर मांग की। कुछ ही देर बाद प्रदर्शन स्थल पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने सभी नर्सों को हिरासत में लिया। लेकिन इसी बीच दो नर्सों की तबियत बिगडने से माहौल और भी ज्यादा गहमागहमी वाला हुआ। जहां बेहोश नर्सों को आरएमएल और लेडी हार्डिंग हास्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं, अन्य प्रदर्शनकारियों को पुलिस मंदिर मार्ग थाने लेकर पहुंची।

अवैध रूप से बनीं 41 दुकानें ढहाई

कुछ दिन पहले दुकान मालिकों को भेजा गया था नोटिस

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बृहस्पतिवार को कोंडली इलाके में निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों के खिलाफ अधिकारियों ने कार्रवाई की। इस दौरान 41 दुकानों को निगम ने तोड़ दिया। शाहदरा साउथ जोन उपायुक्त अतीक अहमद ने बताया कि मयूर विहार फेज-3 स्थित पॉकेट डी-2, जनता फ्लैट कोंडली में लोगों ने अवैध रूप से निगम की जमीन पर कब्जा कर कई दर्जन दुकानें बना ली थीं। इसी को लेकर कुछ दिन पहले अवैध रूप से बनी दुकान मालिकों को इन दुकानों को खाली कराने के लिए नोटिस भी भेजे थे। इसी को देखते हुए निगम के अधिकारी पुलिस बल के साथ तीन जेसीबी मशीनों के साथ अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंचे।

अगले बजट में किया जाएगा एसएमसी के लिए फंड का प्रावधान

एसएमसी को पैसा देगी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को छोटे काम के लिए पैसा देगी। उन्होंने कहा कि एसएमसी के पास बहुत सारे काम हैं जिसके लिए सरकार अब उन्हें पैसा देगी ताकि छोटे छोटे काम एसएमसी अपने स्तर पर करा सकेगी। मुख्यमंत्री एसएमसी सदस्यों के साथ आयोजित कार्यस्र5म में इन सदस्यों के विचार जान रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि मैं व मनीष सिसोदिया राजधानी के कई स्कूलों में गए थे, पता लगता है कि साइंस या गणित या फिर अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। अब चाहते हुए भी 6000 टीचर की फ़ाइल ऊपर नीचे होते होते दो से तीन साल लग जाते हैं। अगर ऐसी कमी हो तो एसएमसी को पावर होनी चाहिए कि वे अपना टीचर तुरंत रख लें। मैं मुख्य सचिव को कहता हूं कि इसको जल्दी लागू करवा दें । सरकारी मशीन बहुत धीरे चलती है फिर भी हम धक्का मार रहे हैं। छोटी मोटी बात हो, जैसे सफाई नहें है तो सफाई कर लें। टीचर की कमी हो तो इधर उधर से जुगाड़ कर लें।

ये पुण्य का काम है सभी स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐप्प बनाना आसान है उसे लागू करना मुश्किल है। एप्प में 24 घण्टे में ही हज़ारो शिकायतें आ जाएंगी, मेरा शिक्षा विभाग से अपील है कि एक एक सुझाव शिकायत पर काम होना चाहिए, अगर ये लागू हो गया तो उसका बड़ा फायदा होगा, एसएमसी का फैसला सरकार के लिए बाध्य होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दो साल एसएमसी ने बहुत अच्छा काम किया है।

एसएससी ने अर्थशास्त्र का शिक्षक नहीं मिलने पर डीयू के टीचर को ही पढ़ाने के लिए बुला लिया। सरकार ये काम करती तो काफी समय लग जाता। सफाई अभियान चला तो विभाग ने समय पर काम नही किया, लेकिन एसएमसी ने खुद सफाई कर दी। सरकार ने एक्ट के तहत एसएमसी को ताकत दी है, इसमे सभी स्कूल बड़े बोर्ड में इसको लिखवा दें।

सरकार की ग्रांट का सही इस्तेमाल, स्कूल के विकास की योजना, एसएमसी इलाके में क्या शिक्षा का स्तर है इसे बताएगी, टीचर पर निगाह रखेगी, टीचर की क्या क्या समस्या है इसे भी बताएगी।

नागरिकता के दैनिक व्यवहार के बिना लोकतंत्र का दैनिक निर्वाह हो ही नहीं सकता।
-राल्फनेडर

विरोध का कोई औचित्य

राज्य सभा में सदन के नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के साथ गतिरोध के अंत से पूरे देश को सुकून मिला है। देश चाहता था कि संसद अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चले, वहां बहस हो तथा जो विधेयक पेश हों, उन पर सबकी राय आए तथा वह आवश्यक संशोधनों के साथ पारित हो जाए। जैसा हम जानते हैं कि गतिरोध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात चुनाव के दौरान दिए गए उस भाषण पर पैदा हुआ था कि जिसमें उन्होंने मणिशंकर अय्यर के घर पर रात्रि भोज गोष्ठी में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की उपस्थिति पर प्रश्न उठाया था। विपक्ष के नाते कांग्रेस की रणनीति थी कि इस पर किसी तरह सरकार को झुकाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो गतिरोध कायम रखा जाए। सरकार ने इसे समझा और जेटली के माध्यम से बयान दिलवा दिया कि मोदी की मंशा डॉ. सिंह की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना नहीं था। जेटली के यह कहने के बाद कि हम इन नेताओं का और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का बहुत सम्मान करते हैं। विरोध का कोई औचित्य भी नहीं रह गया था। हालांकि कांग्रेस ने आरंभ में प्रधानमंत्री द्वारा माफी की मांग की थी जिसे सभापति ने खारिज कर दिया था। तो कांग्रेस भी अपनी मांग से एक कदम पीछे हटी और सत्ता पक्ष ने भी ऐसा बयान दिया जिससे वे शांत हो जाएं। संसदीय लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। किसी एक ध्रुव पर हठ के साथ टिके रहने से लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। सबको अपने रु ख में नरमी लाना पड़ता है। विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने में कोई समस्या नहीं है। यह होना ही चाहिए। विपक्ष की भूमिका में यह निहित है। किंतु यह बहस के माध्यम से होना चाहिए। किसी एक मुद्दे को लेकर संसद को स्थायी रूप से ठप्प कराने से लोकतंत्र ठप्प हो सकता है। यह किसी के हित में नहीं होगा। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकलने दिया तथा सदन के नेता के ऐसे बयान को पर्याप्त मानकर गतिरोध खत्म कर दिया। हालांकि ऐसा पहले होता तो और बेहतर होता। छोटे अंतराल के लिए आहूत संसद का इतना दिन नष्ट हो गया। कांग्रेस को अपना विरोध दर्ज कराने के बाद इसे इतना खींचना नहीं चाहिए था। संसद चले यह सबके पक्ष में है। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका तभी मिलता है जब संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलती है।

ऋण कार्यक्रम

सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में बाजार से दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने का फैसला पहली नजर में चिंतित करता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इससे बजट 2017-18 में रखे गए निवल कर्ज के लक्ष्य में हालांकि कोई बदलाव नहीं होगा,लेकिन इससे हमारा समाधान नहीं हो सकता। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ऋण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, जिसे तकनीकी शब्दावली में जी-सेक कहते हैं, के जरिए 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने का फैसला किया है। इससे टी-बिल्स के जरिए जुटाई जाने वाली राशि मार्च, 2018 तक घटकर 25,006 करोड़ रुपये रह जाएगी। इसका मौजूदा संग्रह 86,203 करोड़ रुपये है। ध्यान रखिए, टी-बिल्स एक साल से कम समय की प्रतिभूतियां होती हैं, जबकि दिनांकित प्रतिभूतियां पांच साल से अधिक समय में परिपक्व होती हैं। वित्त मंत्रालय के बयान को स्वीकार करें तो सरकार अब से लेकर मार्च, 2018 तक शुद्ध रूप से अतिरिक्त ऋण नहीं जुटा रही है। बजट 2017-18 में सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमश: 5.80 लाख करोड़ रुपये और 4.23 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। इसमें से 3.48 लाख करोड़ रुपये शुद्ध रूप से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों से और 2,002 करोड़ रुपये टी-बिल्स से जुटाए जा रहे हैं। इस दौरान सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमश: 5,21,000 करोड़ रु. और 3,81,281 करोड़ रु. रहा है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 26 दिसम्बर, 2017 तक बाजार से उधार तय कैलेंडर के अनुरूप है। सरकार जो भी कहे, सच यह है कि जीएसटी से राजस्व प्राप्ति नवम्बर माह में सबसे कम रहने से बजट गड़बड़ा गया है। सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 और 12 प्रतिशत कर दिया है। इस कारण सरकार को पर्याप्त आय नहीं हो रही है और खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। एक ओर आपने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है और दूसरी ओर आपका राजस्व घट रहा है। उसे पूरा करने के लिए आप कर्ज ले रहे हैं तो यह परोक्ष राजकोषीय घाटा ही हुआ। यह स्थायी निदान नहीं हो सकता। सरकार एवं विपक्ष को स्थायी निदान खोजना चाहिए।

अर्थव्यवस्था गतिशील होगी

नियंतण्र संगठन जीआरडीआई ने कहा है कि वर्ष 2018 में टॉप-30 विकासशील देशों की रैंकिंग में कारोबारी सरलता के मद्देनजर भारत के पहले क्रम पर बने रहने की संभावना है। भारत की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित हुई कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारत का आर्थिक परिदृश्य बेहतर होगा। 26 दिसम्बर को ब्रिटेन की नियंतण्र रिसर्च संस्था सेंटर फॉर इकनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बदले हुए सकारात्मक आर्थिक एवं कारोबारी परिदृश्य के कारण 2018 में ब्रिटेन व फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए

सतीश पेडणोकर

भारत में 2018 में नौकरियां बढ़ेंगी और वेतन वृद्धि 10 से 15 फीसद होगी। निर्यात संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में निर्यात बढ़ेंगे। निर्यातकों को दिए गए 8450 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन से निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा। ख्यात नियंतण्र संगठन जीआरडीआई ने कहा है कि वर्ष 2018 में टॉप-30 विकासशील देशों की रैंकिंग में कारोबारी सरलता के मद्देनजर भारत के पहले क्रम पर बने रहने की संभावना है। भारत की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित हुई कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारत का आर्थिक परिदृश्य बेहतर होगा।

26 दिसम्बर को ब्रिटेन की नियंतण्र रिसर्च संस्था सेंटर फॉर इकनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बदले हुए सकारात्मक आर्थिक एवं कारोबारी परिदृश्य के कारण 2018 में ब्रिटेन व फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए डॉलर के हिसाब से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। जापान की नियंतण्र वित्तीय सेवा कंपनी नमुरा और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ''मूडीज' ने कहा है कि वर्ष 2018 में भारत की विकास दर करीब 7.5 फीसद होगी। वर्ष 2018 में भारतीय शेयर बाजार में तेजी जारी रहने की रिपर्टे भी प्रकाशित हुई हैं। कहा गया है कि वर्ष 2018 में सेंसेक्स 40 हजार की ऊंचाई पर पहुंच सकता है।

रोजगार संबंधी सलाह देने वाली कंपनी मैनपॉवर ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मे 2018 में नौकरियां बढ़ेंगी और वेतन वृद्धि 10 से 15 फीसद होगी। निर्यात संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में निर्यात बढ़ेंगे। निर्यातकों को दिए गए 8450 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन से उनको बड़ा फायदा होगा। ख्यात नियंतण्र संगठन ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) ने कहा है कि वर्ष 2018 में टॉप-30 विकासशील देशों की रैंकिंग में कारोबारी सरलता के मद्देनजर भारत के पहले क्रम पर बने रहने की संभावना है।

निसंदेह वर्ष 2018 में कई सकारात्मक पक्ष भारत की आर्थिक संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश और दुनिया के अधिकांश आर्थिक-वित्तीय संगठन और अर्थ विशेषज्ञ का मत है कि यद्यपि नोटबंदी की शुरुआत में आम लोगों से लेकर उद्योग-कारोबार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्ष 2018 में नोटबंदी के लाभ दिखाई देंगे। पिछले वर्ष के अंतिम सोपान पर सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 9 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम आर्थिक पैकेज को जो ऐलान किया है, उसके लाभ भी 2018 में दिखाई देने लगेंगे।

आर्थिक पैकेज के तहत 6.92 लाख करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सड़क निर्माण परियोजनाएं हैं। इसकी धुरी भारतमाला परियोजना होगी, जिसमें 34 हजार किमी लंबी सड़कें बनेंगी। इस पर 5.35 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके जरिए देश में हाईवे और एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जाएगा। वस्तुत: सरकार ने न्यू इंडिया की नींव रखते हुए अर्थव्यवस्था के लिए जो नौ लाख करोड़ रुपये के पैकेज का डोज दिया है, उससे वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। बैंकिंग सुधार के तहत सरकार ने बैंकों के .2.11 लाख करोड़ रुपए की जो नई पूंजी दी है, उसके लाभ भी 2018 से दिखाई देने लगेंगे। वर्ष 2018 में देश में कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी का परिदृश्य दिखाई देने की पूरी संभावना है। नीति आयोग द्वारा की गई कृषि व किसानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा में कहा गया कि देश में करीब 80 फीसद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था से बाहर हैं। कई तो उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पाते। ऐसे में कृषि व किसानों के हितों पर वर्ष 2018 में सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार ने भी संकेत दिया है कि वह नए वर्ष 2018 में खेती किसानी के हित में महत्त्वपूर्ण कदम उठाएगी। केन्द्र सरकार ने 2022 तक कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आमदनी दोगुनी करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। वर्ष 2018 में ग्रामीण इलाकों में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में आय बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण से रोजगार के नए अवसर तैयार करने की रणनीति प्रस्तुत की है। ऐसे में अब नए वर्ष 2018 में सरकार को कल्याणकारी आर्थिक सुधार की डगर पर आगे बढ़ते हुए किसानों एवं श्रमिकों के साथ-साथ आम आदमी को लाभान्वित करना होगा।

नए वर्ष 2018 में सरकार को एक ओर घरेलू मांग के निर्माण के लिए उद्योग-कारोबार को प्रोत्साहन देना होगा, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। देश में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के अधिक प्रयास करने होंगे। वर्ष 2018 की शुरुआत से ही देश में लोगों को रोजगार देकर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क, आवास, बंदरगाह, विद्युत निर्माण आदि क्षेत्रों की कार्यरत योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का अभियान शुरू किया जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं पर जहां अधिक आवंटन जरूरी होगा, वहीं किसानों के लिए कर्ज भुगतान अवधि और ब्याज दर में ढील देनी होगी। मनरेगा पर आवंटन बढ़ाना होगा। चूँकि कृषि निर्यात वर्ष 2017 में घटकर महज 33 अरब डॉलर रह गया है, अतएव पर्याप्त मात्रा में घरेलू उपज का निर्यात किए जाने के लिए किसानों को निर्यात प्रोत्साहन दिए जाने होंगे। वर्ष 2018 में उद्योग-कारोबार के लिए जीएसटी को और सरल बनाना होगा। टैक्स रिफ्ंड के लिए मैन्युअल रिकॉर्ड और प्रक्रिया की बड़ी खामी को दूर करना होगा। वास्तविक व्यवहार में आ रही जीएसटी दरों से संबंधित कई उलझनों का निराकरण किया जाना होगा। सरकार और कारोबारियों के बीच तालमेल व सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। जीएसटी की स्लैब चार से घटाकर तीन किए जाने पर विचार मंथन अवश्य होना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि आयकर एवं प्रत्यक्ष कर पर गठित नया कार्यबल तय छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। सरकार एक प्रभावी प्रत्यक्ष कर पण्राली के तहत प्रत्यक्ष कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनाएगी। नए आयकर कानून में कर की प्रभावी दर को घटाने, प्रशासनिक बोझ को आसान बनाने और विवादास्पद मसलों पर मुकदमेबाजी घटाने पर ध्यान दिया जाना होगा। इन सबके साथ-साथ वर्ष 2018 में अब बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करनी होगी, काले धन का बकाया इलाज पूरा करना होगा। अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करनी होगी। हम आशा करें कि सरकार वर्ष 2018 में चौतरफा कदम आगे बढ़ाएगी, जिससे देश 7.5 फीसद विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

चलते चलते

''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'

गरीब वर्ग को यह संवेदना सरकार से मिलनी चाहिए, लेकिन हालात असंवेदनशीलता के ये हैं कि गरीब की बचत योजनाओं पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वक्र दृष्टि पड़ गयी। वित्त मंत्रालय की रीति-नीति यह है

चुटकी संवेदना का अकाल ! जी हां, चुटकी भर संवेदना की आवश्यकता देश के बहुसंख्य गरीब वर्ग को है। गरीब वर्ग को यह संवेदना सरकार से मिलनी चाहिए, लेकिन हालात असंवेदनशीलता के ये हैं कि गरीब की बचत योजनाओं पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वक्र दृष्टि पड़ गयी। वित्त मंत्रालय की रीति-नीति यह है कि लघु बचत योजनाओं के ब्याज पर भी कटौती कर दी गयी। इसमें भारत सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आया क्योंकि एक ओर केन्द्र सरकार का कथन है कि ''सबका साथ-सबका विकास' तो वहीं लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती कर अपने ही स्लोगन का झुठला दिया। गौरतलब है कि लघु बचत योजनाओं में खास तौर से गरीब तबका ही जुड़ता है। कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटी-लघु बचत करता है तो कोई बेटी की शादी-विवाह के थोड़े-थोड़े पैसे बचा कर बचत करता है। भले ही ब्याज दरों में यह कटौती आंशिक हो लेकिन गरीब वर्ग की बचत में बड़ा फर्क डालेगी। सरकार के इस फैसले से ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का स्लोगन भी कहीं न कहीं धुंध में छिपता नजर आता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र हो या लोक भविष्य निधि हो.. इन सभी बचत योजनाओं से प्रमुखता से जुड़ने वाला गरीब वर्ग ही होता है। ब्याज दर की यह कटौती भले ही 0.2 फीसद है। लेकिन बचतकर्ता की कुल जमा में ब्याज सहित फर्क डालेगी। हालात ये हैं कि किसान विकास पत्र को भी इस छेड़छाड़ से नहीं छोड़ा गया। किसान हित-किसान कल्याण का ढ़ोल पिटने वाली सरकार ने किसान विकास पत्र की भी ब्याज दरों में कटौती की है। यदि किसान विकास पत्र की धनराशि का उपयोग किसान कल्याण में करने की कोई योजना है तो किसान की कल्याणकारी योजनाओं पर फर्क आयेगा। बालिकाओं से ताल्लुक रखने वाली बचत योजना ''सुकन्या समृद्धि योजना' की ब्याज दर में कटौती की घोषणा है। अब गम्भीर सवाल उठता है कि ऐसे में बेटियां कैसे बढ़ेंगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? केन्द्र सरकार को कम से कम गरीब वर्ग से ताल्लुक रखने वाली बचत योजनाओं की ब्याज दरों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि समाज के सबसे निम्न तबके का विकास होगा तभी सबका साथ सबका विकास स्लोगन सार्थक होगा।

सत्संग

''चित्त वृत्ति निरोधः'

आप हर चीज को उसी तरह समझते और महसूस करते हैं, जैसी वह है, तो लोग आपको दिव्यदर्शी या मिस्टिक कहते हैं। अगर आप जीवन को वैसे नहीं देखते, जैसा वह है तो इसका मतलब है कि आप मिस्टिक नहीं, मिस्टेक हैं।(गलती कर रहे हैं)। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है, वह उस तरह से इसलिए घटित होता है, क्योंकि वह आपके मन के पर्दे पर उसी तरह से प्रतिबिंबित होता है। पतंजलि ने योग की बहुत ही आसान और टेक्निकल परिभाषा दी। जब लोगों ने पूछा, ''योग क्या है?' तो उन्होंने जवाब दिया, ''चित्त वृत्ति निरोध:'। जिसका मतलब है कि जब मन के भीतर के सारे बदलाव खत्म हो जाएं तो वही योग है। तभी आप हर चीज को ठीक वैसा ही देखेंगे, जैसी वह है। अगर आप हर चीज को उसी रूप में देखें, जैसी वह है, तो आपको इस सृष्टि के साथ भी एकात्मकता दिखाई देगी। मन में हलचल और अतीत का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक और समस्या हो सकती है, अगर आपके पास ऐसा कोई आइना है, जो चीजों को याद रखता हो फिर तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक अच्छे आइने के बारे में पहली चीज यह है कि इसे पूरी तरह से सपाट होना चाहिए। दूसरी चीज इसे अपने भीतर कुछ नहीं रखना चाहिए।

केवल तभी यह आपको चीजें वैसी दिखाएगा, जैसी वास्तव में वह हैं। हम सब लोगों को भी यही करना होगा। अपने मन को सपाट व समतल करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी और देखना होगा कि इसमें अतीत का कुछ भी संजोया हुआ बाकी न रहे। अगर आप चीजों को सहज रूप से देखना सीख लें, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज को बिलकुल वैसा ही देखेंगे, जैसी वह है। इसके लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। भेदभाव की स्थिति में सत्य को जानना संभव नहीं है। हर चीज को सम्मान के साथ देखना शुरू कीजिए। यह तरीका भी काम करेगा। असली समस्या भेदभाव की है कि यह बेहतर है और वह कमतर है, यह अच्छा है और वह बुरा है। इस स्थिति में तो आप कभी अस्तित्व की असलियत को जान ही नहीं पाएंगे। आपका मन भी बंट जाएगा। एक बार अगर आपका मन विभेदकारी हो गया तो यह स्थिति एक टूटे हुए आइने सी होगी।

फोटोग्राफी...

189 फोटो ग्राफ को मिलाकर 160 घंटे में बना मैनहटन स्का ईलाइन का यह फोटो

यह 602 मेगापिक्सल का कम्पोजिट फोटोग्राफ है, जिसे 189 अलग-अलग फोटोग्राफ्स से मिलाकर बनाया गया है। फोटोग्राफर, इंजीनियर और आंत्रप्रेन्योर डैन पीच को इस फोटोग्राफ को बनाने में 160 घंटे का समय लगा। वे अत्यधिक हाई रेजॉल्यूशन फोटो ग्राफिक्स आर्टवरक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर को चुना। इसमें मैनहटन की गगनचुंबी इमारतों (स्का ईलाइन) के फोटोग्राफ शामिल किए गए हैं। 602 मेगा पिक्सल के इस फोटोग्राफ को बनाने में 9 हजार 563 मेगा पिक्सल के डेटा का उपयोग किया गया है।
vastphotos.com

विकास की नीति

मौजूदा समय में सरकार की प्रक्रियाएं नागरिकों पर केन्द्रित होते हुए एक नये डिज़ायन और सिंगल विंडो संस्कृति में तब्दील हो रही है। सुशासन में निहित ई-गवर्नेंस की ज्यादातर पहल में बिज़नेस मॉडल, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप समुचित तकनीक और स्मार्ट सरकार के साथ इंटरफेस उद्यमिता इत्यादि का उपयोग किया जाता है, लेकिन आगे बढ़ने या आरम्भिक सफलता को दोहरा पाने में यह पूरी तरह अभी सफल नहीं है। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जो शासन को अधिक खुला, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाता है ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देश की जनता को दिल खोलकर विकास दें। मानवाधिकार, सहभागी विकास और लोकतांत्रिकरण का महत्त्व सुशासन की सीमाओं में आते हैं। 1991 में उदारीकरण के तीन दशक के बाद यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार, नागरिक घोणापत्र, ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ई-याचिका तथा ई-सुविधा समेत लोकहित से जुड़े तमाम संदर्भ सुशासन की दिशा में उठे कदम ही हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं कि सुशासन के कोर में सरकार की जिम्मेदारी कहीं अधिक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सुशासन और इसके समक्ष खड़ी चुनौतियां दूसरे देशों की तुलना में भिन्न हैं। जाहिर है न्याय, सशक्तीकरण, रोजगार एवं क्षमतापूर्वक सेवा प्रदान करने से जब तक समाज के प्रत्येक तबके को गरीबी, बीमारी, शिक्षा, चिकित्सा समेत बुनियादी तत्वों को हल नहीं मिलता तब तक सुशासन की परिभाषा अधूरी रहेगी। सुशासन की क्षमताओं को लेकर ढेर सारी आशाएं हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आते ही सुशासन को लेकर कुछ सक्रिय दिखाई दिये। 25 दिसम्बर को क्रिसमस दिवस के रूप में ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में भी मनाने की प्रथा रही है। मोदी वर्ष 2014 में इस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी को और अधिक सम्मान देने के लिए किया गया। तभी से 25 दिसम्बर ने एक नई अवधारणा व विचारधारा से पोषित हो सुशासनिक राह ले लिया। सफल और मजबूत मानवीय विकास को समझने के लिए सुशासन के निहित आयामों को जांचा-परखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल बिता चुके हैं। स्किल डवलेपमेंट मामले में चीन से ही नहीं हम दक्षिण कोरिया जैसे छोटे राष्ट्र से भी पीछे हैं। भारत के नगरों और गांवों के विकास के लिए वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन इस दिशा में उठाया गया कदम था। प्रधानमंत्री मोदी न्यू इण्डिया की बात कर रहे हैं लेकिन इस पर शक कम होने के बजाय गहराता है। जब तक कृषि क्षेत्र और इससे जुड़ा मानव संसाधन भूखा-प्यासा और शोषित महसूस करेगा। सुशासन के लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी है और ऐसा तभी होगा जब पूरी पण्राली पारदर्शी और ईमानदार हो। पुरानी पड़ चुकी नौकरशाही के ढांचे में नई जान फूंकना मोदी के लिए भी न पहले आसान था और न अब। हां कोशिश बड़ी जरूर की जा रही है। यह कहना सही है कि डिजिटल गवर्नेंस का दौर बढ़ा है। भारत में नवीन लोकप्रबंधन की पण्राली के रूप में यह संचालित भी हो रहा है पर सुशासन के भाव में तब बढ़ोत्तरी होगी जब सरकार के नियोजन तत्पश्चात होने वाले क्रियान्वयन का सीधा लाभ जनता को मिले। गैस की सब्सिडी इसी के माध्यम से सीधे जनता को मिल रही है पर सरकार जिस प्रकार सब्सिडी हटा रही है और मार्च 2018 तक लगभग इसे समाप्त करने की कोशिश में है। यह सुशासन नहीं बल्कि यह एक आर्थिक गणना है जिसमें लोक कल्याण कम आर्थिक मुनाफे पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

बीएचयू परिसर बवाल में 13 छात्र निलंबित, एजुकेशनल सुविधाओं को किया निरस्त

बनारस (ईएमएस)। बीएचयू परिसर में बवाल करने के मामले में छात्र नेता आशुतोष सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीएचयू प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार देर रात प्रशासन ने १३ छात्रों को निलंबित कर दिया। बीते २० दिसम्बर को लंका पुलिस ने कई मामलों में वांछित समाजवादी छात्रसभा के नेता आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में एक दर्जन से अधिक छात्रों ने घंटेभर परिसर में उत्पात मचाया। एक निजी स्कूल बस में आग लगा दी और कई बाइकों को तोड़ दिया था। मरीजों, तीमारदारों एवं आमलोगों से भी मारपीट की गई। इसको लेकर बीएचयू प्रशासन ने लंका थाने में गौरव कुमार, शुभम तेवतिया, बिट्टू कुमार सिंह, गुलाम सरवर, प्रवीण राय, गौरव कुमार, अभिजीत मिश्र, रुदप्रताप सिंह, सौरभ राय, प्रतीक तिवारी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, सत्यम राय, धीरज सिंह, हिमांशु प्रभाकर समेत 15 छात्रों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि दो छात्र मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में छात्र गुलाम सरवार का नाम सामने आया। इसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की लेकिन गुलाम सरवर को छोड़कर किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

दलित युवकों के हंगामे के बीच अठावले ने बीच में छोड़ा कार्यक्रम

गाजियाबाद (ईएमएस)। इंदिरापुरम के सेंट टेरेसा स्कूल में ग्रेट जाटव महासभा के कार्यक्रम में एक युवक द्वारा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से संविधान को लेकर सवाल पूछने के बाद हंगामा हो गया। जब उसे शांत कराने का प्रयास किया गया तो उसके समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वे शांत नहीं हुए तो केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम छोड़ कर चले गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले शाम को इंदिरापुरम के सेंट टेरेसा स्कूल में ग्रेट जाटव सभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान वह समाज के युवाओं को सम्मान देने लगे तो एक युवा ने उनसे सम्मान लेने से इन्कार कर दिया। इस दौरान एक युवक ने उनसे प्रश्न किया कि भाजपा नेता लगातार डॉ. बीआर अंबेडकर और संविधान को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा संविधान के दायरे में रहकर सभी काम करती है और संविधान का पूरा सम्मान करती है। जिन लोगों ने विवादित बयान दिया है, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट भी की है। संविधान को बदलने का प्रश्न ही नहीं है।

जिलाधिकारी ने रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण

औरैया(ईएमएस)। जिला अधिकारी श्रीकान्त मिश्रा ने देर रात नगर पालिका परिषद की ओर से शहर में सरकारी बस स्टैण्ड के ठीक सामने बनाए गए निशुल्क रैन बसेरा का निरीक्षण कर वहा पर की गई समस्त व्यवस्थाओं को परखा।उन्होंने ईओ नगर पालिका से कहा कि रैन बसेरे मे आने वाले व्यक्तियों के लिये पानी,शौचालय आदि की नियमित साफ-सफाई की जाए और रैन बसेरा में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम रजिस्टर में लिखा जाए।अलाव को देर रात तक जलाया जाए जिससे रैन बसेरे में आने वाले व्यक्ति ठंड से बच सके। ईओ संजय कुमार ने जिलाधिकारी को बताया कि नगर में कुल 16 जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है जिसमें रोडवेज बस स्टैंड, खानपुर चौराहा,सरकारी अस्पताल,सत्ती तालाब, जेसी चौराहा,जालौन चौराहा,कानपुर चौराहा,संजय गेट,ब्रह्म नगर चौराहा,सदर बाजार,पक्का तालाब, काली देवी मंदिर,जमाल शाह,गौरैया तालाब जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर निरंतर अलाव जलाया जा रहा है।जिस पर उन्होंने ईओ को निर्देश दिए कि नगर में जलने वाले सभी अलाव का निरीक्षण करते रहे।साथ ही कहा कि रैन बसेरे को स्थान चिन्हित कर स्थाई बनाया जाए जिससे राहगीर रैन बसेरे में आराम कर सके।

कुम्भ के दौरान मेला क्षेत्र तक निशुल्क शटल बसें चलाई जाएंगी

इलाहाबाद (ईएमएस)। मंडलायुक्त आशीष गोयल की अध्यक्षता में कुम्भ की तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया ?कि कुम्भ मेले के दौरान सभी पार्किंग स्थलों से मेला क्षेत्र तक नि:शुल्क शटल बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ चार हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। गंगा दर्शन के लिए बक्शी बांध रोड के किनारे सीमेंट की बेंच बनाई जाएंगी। इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई। मंडलायुक्त ने सभी आरओबी व फ्लाईओवरों के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। फूलपुर में आरओबी का निर्माण न शुरू होने पर सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक गेंदालाल को चेतावनी जारी की। उन्होंने इस आरओबी के लिए टेंडर की प्रक्रिया अब तक नहीं पूरी होने का कारण पूछा। सभी स्थायी कार्यों को नौ महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। नवागत मेलाधिकारी से भी मंडलायुक्त ने कहा कि सभी कार्यों की मॉनीटरिंग लगातार होनी चाहिए। तभी काम समय से पूरा हो पाएगा। मंडलायुक्त ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मेला क्षेत्र के आसपास जमीन तलाश कर हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने माघ मेला क्षेत्र में एक हजार और सोडियम लाइट लगाने का निर्देश पावर कापोरेशन के अधिशासी अभियंता को दिया।

तीन तलाक के बिल पर समर्थन कर राहुल कर सकते हैं प्रायश्चित: सुशील मोदी

पटना (ईएमएस)। गुरुवार को लोकसभा में सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक के विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मोदी सरकार इस मुसलमान महिलाओं की जीत बात रही है। वहीं विपक्ष आधे मन से सरकार के साथ खड़ा हैं। इसी मामले में शुक्रवार को भाजपा नेता व बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लोकसभा में तीन तलाक का बिल पास होने पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश की 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने के लिए राजनीतिक नफा-नुकसान की फिक्र किए बिना एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर तीन तलाक प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। 22 अगस्त 2017 के ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने इस अन्याय को गैरकानूनी बताया था। सरकार ने तीन तलाक पर लोकसभा में बिल पास कर मुस्लिम महिलाओं से वादा निभाया। इस मौके पर सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दहेज उत्पीड़न में सजा हो सकती है तो तीन तलाक में क्यूं नहीं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग कर तलाकशुदा शाहबानों को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर कर दिया था। 31 साल बाद राहुल गांधी तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले बिल का समर्थन कर अपने पिता के राजनीतिक अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं।

माघ मेला में स्वामी स्वरुपानंद को मेले में जगह नहीं दी उप्र सरकार ने

स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती करेंगे बहिष्कार

इलाहाबाद(ईएमएस)। प्रयाग राज के नाम से प्रसिद्ध इलाहाबाद में माघ मेला की शुरुआत दो जनवरी 2018 से होने जा रही है। इस बार माघ मेले में करीब चार करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को जमीन नहीं दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेला प्रशासन की ओर से माघ मेला क्षेत्र में ज्योतिष्पीठ की जमीन नहीं दिए जाने से नाराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले ही मेले का बहिष्कार करने का मन बनाया हुआ है। वहीं खबर है कि एकादशी पर 11 जनवरी को स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती इलाहाबाद आएंगे। स्वामी स्वरूपानंद के मेले का बहिष्कार किए जाने वाले निर्णय से जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ उनके श्रद्धालुओं में भी रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि माघ मेला का हिन्दू समाज में विशेष

महत्व है। इसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। इसलिए स्वामी स्वरुपानंद को उप्र सरकार द्वारा जमीन नहीं दिए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।

कुछ माघ मेले के बारे में मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में माघ मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इलाहाबाद में 2 जनवरी से मेला का आयोजन किया जा रहा है। माघ मेला हिन्दू समाज का ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। वैसे तो नदी में या सागर में स्नान करते हुए पूजा-पाठ करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मेला स्थल में धार्मिक गतिविधियों के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्त शिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। इस कारण मेले में हर समुदाय के लोग आते हैं और खरीद-फरोख्त के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार धार्मिक महत्तव के अतिरिक्त यह मेला एक विकास मेला भी है तथा इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार आदि स्थलों का माघ मेला विश्वस्तर पर प्रसिद्ध है।

बिल्डर संजीव के ऑफिस में छापा, पकड़ी गई 25 करोड़ की पुरानी करंसी

मेरठ (ईएमएस)। नोटबंदी के एक साल पूरे होने के बाद भी अभी देश के कई जगह से पुराने नोट पकड़े जाने की खबरें आ रही है। इसी बीच मेरठ जनपद में शुक्रवार दोपहर को एक बिल्डर के ऑफिस से 25 करोड़ रुपये की पुरानी करंसी पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी करंसी को बदलने के लिए यहां डील हो रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर वहां से करंसी बरामद की ली। वहां से पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में भी लिया है, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, इससे यह साबित होता है कि अब भी पुरानी करंसी को बदलने का खेल चल रहा है। मामला थाना परतापुर क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित राजकमल का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संजीव मित्तल के पास दिल्ली से चार-पांच लोग पुरानी करंसी बदलने के लिए आए हैं। इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारा तो करीब 25 करोड़ रुपये की पुरानी करंसी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि बिल्डर संजीव मित्तल के मेरठ में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस मामले में एसपी सिटी मान सिंह चौहान का कहना है कि पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें परतापुर थाने में रखा गया है। वे ये करंसी कहां से लाए हैं ये पुरानी करंसी किसकी हैं,इसकी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी इसी साल मार्च में शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नोएडा से कार में लाई जा ही 46.5 लाख की पुरानी करंसी जब्त की थी। तब पुलिस ने कार सवार तीन युवकों को पकड़ा था। युवकों के पास से एक हजार के नोटों की 21 गड्डियां और बाकी 25 लाख 50 हजार रुपये के 500 के नोट मिले थे। वहीं,पिछले साल दिसंबर में मेरठ में ही एसटीएफ ने शहर की मेघदूत पुलिया के पास से चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

ये लोग 15 फीसदी के कमीशन पर पुराने नोट लेकर नई करंसी दे रहे थे। इनके कब्जे से 8.80 लाख की नई करंसी बरामद की गई थी। उनके कब्जे से दो- दो हजार के नोट मिले थे।

शिवपाल सिंह यादव युवा वाहिनी ने फूंका सपा नेता नरेश अग्रवाल का पुतला

बस्ती,(ईएमएस)। शिवपाल सिंह यादव युवा वाहिनी उ.प्र. जिलाध्यक्ष राजकुमार उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कम्पनीबाग चौराहे के निकट समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का पुतला फूंका। पुतला जलाने से पूर्व राजकुमार उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि राज्यसभा में जिस प्रकार से नरेश अग्रवाल ने जाधव प्रकरण में बयान दिया वह शर्मशार करने वाला है। एक तरह से वे भारत के सदन में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। उन्होने सदन में अपने बयान से समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। मांग किया कि नरेश अग्रवाल की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय। सपा नेता नरेश अग्रवाल का पुतला फूंकते समय राजकुमार उर्फ पप्पू यादव के साथ इमतियाज अहमद, रितेश गौतम, पवन यादव, नजीर अहमद, शिवम श्रीवास्तव, कादिर भाई, राजू वर्मा, घनश्याम प्रजापति, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, अर्जुन सोनकर, अब्दुल इकराम खान, प्रिन्स यादव, राजू वर्मा, अजय वर्मा, राजेश कुमार के साथ ही शिवपाल सिंह यादव युवा वाहिनी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने लगायी भैलवारा में चौपाल

ललितपुर(ईएमएस)। जिलाधिकारी द्वारा शीतकालीन भ्रमण के दौरान राजस्व ग्राम भैलवारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों को देखा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय को बताया गया कि ग्राम में कुल 70 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया है,जिसमें से 46 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है,09 का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 15 शौचालय प्रस्तावित हैं।राजस्व ग्राम भैलवारा में बनाये गये शौचालयों की ऊंचाई कम होने तथा शौचालयों के हवादार न होने पर उन्होंने एडीओ पंचायत से शौचालयों में सुधार करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से शौचालय निर्माण के बारे में पूछताछ की तथा लाभार्थियों को शौचालयों के उपयोग हेतु प्रेरित भी किया।इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि ग्राम में प्रधानमंत्री आवास हेतु 08 आवासों का लक्ष्य रखा गया है,जिनका निर्माण कार्य छत स्तर तक पूर्ण हो चुका है,जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित को शेष कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।निरीक्षण के उपरान्त ग्राम भैलवारा में जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संध्याकालीन जन चौपाल का आयोजन किया गया।चौपाल के दौरान बताया गया कि ग्राम भैलवारा से बम्हौरी कलां तक 02 किमी सम्पर्क मार्ग पूर्व से कच्चा है जो कि खराब हालत (मरम्मत योग्य) है।विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्राम भैलवारा विद्युतीकृत है,ग्राम में 02 ट्रांसफार्मर तथा 10 पोल स्थापित है।शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय संचालित है,जिसमें कुल 47 छात्र अध्ययनरत हैं,जिन्हें पुस्तक,बैग,ड्रेस तथा जूता-मौजा वितरण हो चुका है एवं मिड डे मील का वितरण नियमित रूप से हो रहा है। स्वच्छ पेयजल एवं हैण्डपम्प स्थापना के तहत बताया गया कि ग्राम में 05 हैण्डपम्प पूर्व से स्थापित हैं जो चालू हालत में हैं।इसके उपरान्त मनरेगा के तहत जानकारी दी गयी कि ग्राम भैलवारा कुल जॉबकार्डों की संख्या 80 है,जिसमें से 55 सक्रिय हैं।

नक्सलियों ने मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले

औरंगाबाद (ईएमएस)। देश के कुछ राज्य हैं जहां नक्सलियों का ताड़व हमेशा ही देखने में मिलाता है। इन्हें राज्य में बिहार भी शामिल है। गुरुवार की शाम बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव हुआ। गुरुवार शाम नक्सलियों ने इलाके में सड़क निर्माण के कार्य में लगी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक,गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहजपुर-सहीयार गांव के पास सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर हमला बोल दिया। नक्सलियों ने इनके साथ मारपीट की और सड़क निर्माण में लगे 5 ट्रैक्टर,1 जेसीबी मशीन और 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के हमले के दौरान मौजूद सभी मजदूर किसी तरीके से अपनी जान बचा कर भाग गए। सूत्रों के मुताबिक,मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया है उससे पिछले कुछ महीनों से नक्सली लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नक्सलियों की मांग को ठुकरा दिया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के तुरंत बाद मदनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए लगातार कॉन्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों ने इलाके में सड़क निर्माण के कार्य में लगी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक,गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहजपुर-सहीयार गांव के पास सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर हमला बोल दिया। गौरतलब है कि, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है वह झारखंड बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद के एसपी सत्यप्रकाश ने कहा कि,घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना में शामिल नक्सलियों की खोज की जा रही है।

जागकता से रूकेगा बाल विवाह प्रशिक्षण कार्यशाला में दि जानकारी

बस्ती (ईएमएस)। बाल विवाह को रोकने के लिये सामाजिक स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वे शिक्षति हांगे बाल विवाह का कलंक समाप्त होता जायेगा। केवल कठोर कानून बना देने मात्र से इस पर अंकुश संभव नही है। यह विचार बाल विकास परियोजना अधिकारी दिलीप कुमार वर्मा ने व्यक्त किया। वे चाइल्ड लाइन द्वारा शुक्रवार को बाल विवाह एक्ट पर चाइल्ड लाइन कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान सम्बोधित कर रहे थे। सीडीपीओ सदर कृष्णेन्द्र यादव ने बाल विवाह से सम्बंधित कानूनों की विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि कानून से अधिक यह एक सामाजिक बुराई है। जागरूकता के आधार पर ही इसे जमीनी धरातल पर रोका जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यशाला को ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव रामललित यादव ने बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी।

भाजपा और कांग्रेस, चोर-चोर मौसेरे भाई: मायावती

लखनऊ (ईएमएस)। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और केंद्र सरकार के साथ-साथ कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान आज खतरे में जरूर है, परंतु यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि संविधान को उसकी सही मंशा के अनुसार लागू करके देश का व्यापक कल्याण करने के मामले में कांग्रेस किसी भी प्रकार से भाजपा एंड कंपनी से कम फेल नहीं रही है। संविधान के पवित्र उद्देश्यों को फेल करने के मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संविधान को खतरा होने के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा, यही सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस की विघटनकारी व हिंदुत्ववादी सोच वाली सरकार में देश का संविधान खतरे में है। यह सभी जानते हैं कि आरएसएस की सोच संविधान व तिरंगा विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान की शपथ लेकर सरकार में तो आ गए हैं, लेकिन इसी संविधान की आड़ में अपनी घोर कट्टरपंथी व जातिवादी सोच को लागू करने में भी ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते।

अमहट पुल निर्माण को लेकर सर्वदलीय धरना जारी चौथे दिन रालोद ने संभाला मोर्चा

बस्ती (ईएमएस)। कुंआनों नदी पर स्थित अमहट पुल का निर्माण कराये जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव सुरेन्द्र सिंह उर्फ छोटे सिंह के नेतृत्व में अनिश्चित कालीन सर्वदलीय धरना चौथे दिन शुक्रवार को भी शास्त्री चौक पर जारी रहा। चौथे दिन राष्ट्रीय लोकदल ने धरने का मोर्चा संभाला। वक्ताओं ने कहा कि जब तक अमहट पुल निर्माण की अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती सर्वदलीय धरना जारी रहेगा। धरने को रालोद के पूर्वान्चल प्रभारी गंगासिंह सैथवार, ओम प्रकाश चौधरी, राधेश्याम, शिवकुमार गौतम, राय अंकुरम, ओम प्रकाश शुक्ल, चन्द्रमणि पाण्डेय के साथ ही पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, चन्द्रभूषण मिश्र, माकपा सचिव का. के.के. तिवारी, सपा जिलाध्यक्ष राजकपूर यादव, रविन्द्र यादव, युसुफ बस्तवी, सत्यराम, दिग्विजय सिंह, डा. फारूख, पप्पू यादव, जितेन्द्र यादव, चन्द्रबदन सिंह, प्रद्युम्न यादव, शेर सिंह, फूलचन्द्र श्रीवास्तव आदि ने सम्बोधित किया। कहा कि पिछले 10 माह से अमहट पुल का निमार्ण न शुरू कराया जाना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सर्वदलीय धरने मं घनश्याम यादव, गिरजेश पाल, डा. देवेन्द्र श्रीवास्तव, ताराचंद पाठक, हीरालाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अनिल सिंह, अखण्ड सिंह, राजेश विश्वकर्मा, पंकज गौतम, भारत यादव, चीनी चौधरी, अब्दुल कासिम, राम बहाल यादव, मो. याकूब खा, जिलेदार, मुश्ताक हुसेन, गुड्डू भाई, राजू, हजरत बाबा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित रहे।

बागपत में गैंगरेप से बचने को निर्वस्त्र दौड़ी युवती, गांववालों ने बचाया

बागपत (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत गांव के जंगल में प्रेमी संग पहुंची युवती से चार युवकों ने गैंगरेप का प्रयास किया। युवती उनके चंगुल से निकल निर्वस्त्र हालत में दौड़कर पास के गांव पहुंच गई। ग्रामीणों ने युवती के परिजनों को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया और जंगल में जाकर उसके प्रेमी को बंधनमुक्त कराया गया है। बिनौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती गुरुवार शाम को अपने प्रेमी के साथ बावली गांव के जंगल में पहुंची। वहां पर चार युवकों ने उन्हें घेर लिया और प्रेमी को बंधक बनाकर उससे मारपीट की है। इसके बाद आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। युवती ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसके साथ भी मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए है।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास

पुलिस द्वारा परेशान करने से 18 से अधिक नींद की दवाई खा लिया

संवाददाता, सूरत। शहर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कडोदरा के एक युवक ने न्याय न मिलने से 18 से अधिक नींद की गोली खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। शुक्रवार को दोपहर कमिश्नर कार्यालय की पार्किंग में से बेहोशी की हालत में मिलने से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

नई सिविल अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरत शहर पुलिस कमिश्नर कार्यालय स्थित पार्किंग में मूलत: बिहार के और इस समय सूरत के कडोदरा में रहने वाला मुनाफ खान बेहोशी की हालत में मिलने पर उसको पुलिस वैन में लादकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि इस तरह का कदन उठाने वाले मुनाफ ने बताया कि उधना और लिंबायत पुलिस द्वारा झूठे केस के आरोप में फंसाने और न्याय न मिलने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। उसने बताया कि उधना और लिंबायत पुलिस द्वारा फर्जी केस में फंसाए जाने के बाद पिछले तीन माह से कमिश्नर कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। अतएव परेशान होकर कमिश्नर कार्यालय की पार्किंग में ही आत्महत्या करने के इरादे से 18 गोलियां खा लिया था।

तीन तलाक विधेयक पास होने पर कपड़ा व्यापारियों ने जताई खुशी

नारकीय जीवन से मुस्लिम महिलाओं को मिली निजात

संवाददाता, सूरत। मुस्लिम समाज की महिलाओं को सदियों से तीन तलाक व हलाला जैसी कुरीति का सामना करना पड़ रहा था। मुस्लिम महिलाओं को हलाला के दौरान मौत से बद्तर हालत से गुजरना पड़ता था। मुस्लिम समाज की महिलाओं की इस नारकीय वेदना को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक, हलाला जैसी कुरीति को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को समाज में गर्व व स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ी और अंतत: गुरूवार को लोक सभा में बिना संसोधन किए तीन तलाक पर विधेयक पारित कर तीन तलाक को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में ला दिया। इस फैसले का एनटीएम कपड़ा मार्केट में कपड़ा कारोबारी बजरंग खण्डेलवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बजरंग खंडेलवाल ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम समाज की महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार मिल गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति तीन बार तलाक कह कर किसी महिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता था। अगर उस महिला को वह दोबारा अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी होता तो उसे हलाला जैसे नारकीय नियम के तहत दूसरे मर्द के साथ निकाह व पति-पत्नी के रिश्ते कायम करने के बाद फिर से तलाक लेकर पुन: पहले पति से निकाह करना पड़ता था।

जो महिला के लिए नारकीय जीवन के समान था। अब वह इस कुरीति से निजात पा गई। बैठक में नेम सिंह राठौर, नंदू सिंह राठौर, राकेश सिंह राठौर, गोपाल रिणवा, भवरलाल, विशाल चुग सहित काफी तादाद में कपड़ा कारोबारी मौजूद थे।

रहस्यमयी ढंग से युवक फांसी पर झूलते मिला

संवाददाता, सूरत। शहर के लिंबायत मीठीखाड़ी का रहने वाला एक 30 वर्षीय युवक किन्ही आज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार मीठी खाड़ी

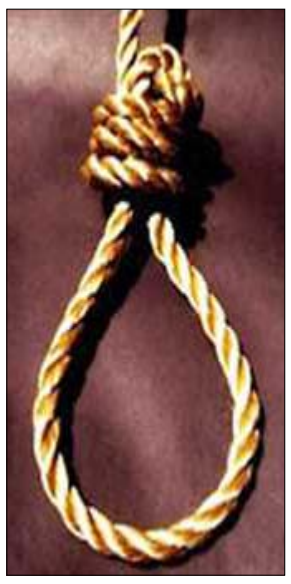

आंबेडकर नगर घर नं. 117 में रहने वाला अल्ताफ इकबाल शनिवार की रात लगभग 11 बजे अपने घर में लगे एंगल के साथ रस्सी से फांसी पर झूलते मिला।

जिससे उसके मित्र शकील ने बेहोशी की हालत में इलाज के लिए उसे अस्पाताल ले गया जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद अल्ताफ को मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में लिंबायत पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

घर के पास बैठी अधेड़ महिला के गले से चेन छीन भागे उचक्के

संवाददाता, सूरत। कतारगांव ललीता चौकड़ी के पास रणछोड़ पार्क सोसाइटी में रहने वाली एक अधेड़ महिला के गले से बाइक पर सवार होकर आए दो उचक्के 60 हजार की चेन झपटकर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कतारगांव रणछोड़ सोसाइटी के घर नं. 277, भाग-2 ललीता चौकड़ी में रहने वाले हितेशभाई अमृतभाई मिस्त्री किसी फर्म में एकाउन्ट का काम करते हैं। इनकी मां गत रोज अपने घर के बगल में थी। उसी समय बाइक पर सवार होकर आए दो उचक्कों में से पीछे बैठा युवक हितेशभाई की मां के गले से करीब ढाई तोला की चेन (कीमत-60.000 रुपए) झपट कर भाग गया। घटना के संदर्भ में हितेशभाई ने कतारगांव पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कपड़ा मार्केट में जेब कतरों का आतंक

क्लर्क की जेब से सवा लाख चोरी कर फरार, सलाबतपुरा थाने में मामला दर्ज

संवाददाता, सूरत। कपड़ा मार्केट में ठगों, उच्चकों व जेब कतरों का साम्राज्य कायम है। आए दिन कोई न कोई व्यापारी, दुकानदार व राहगीरों को अपना निशाना बना कर उसके पास से मोबाइल, कै श व कपड़ों का पोटला चोरी कर फरार हो जाते हैं। बीते दिन दोपहर कपड़ा मार्केट में काम करने वाले युवक को अपना शिकार बनाकर चोर उसके पास से एक लाख 35 हजार चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने सलाबतपुरा थाने में अनजान चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

सलाबतपुरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार पूणागांव इलाके के विवेकानंद सोसायटी रूम नंबर 218 निवासी बाबूलाल मूलचंद पारीख कपड़ा मार्केट में नौकरी करता है। उसके सेठ ने उसे बीते दिन दोपहर एक लाख 35 हजार का चेक देकर बैंक से कैश लाने को भेजा था। बाबूलाल पारीख बैंक से कैश लेकर लौट रहा था। वह जैसे ही पद्मावती मार्केट के पास पहुंचा, इसी बीच कोई चोर उसकी जेब से 1 लाख 35 हजार चुराकर फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की जानकारी अपने सेठ को दी। बाबूलाल पारीख अपने सेठ के साथ सलाबतपुरा थाने पहुंचकर चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। वहीं गोडादरा के व्रजधाम सोसायटी निवासी कपड़ा कारोबारी राजकुमार किशनजी सोलंकी की स्वदेशी मार्केट में दुकान नंबर 518-519 में महावीर प्रिंट के नाम से साड़ी की दुकान है। वह गत 24 नवंबर सुबह 11.30 बजे सूरत टेक्सटाइल मार्केट में स्थित बैंक ऑफ बडौदा की शाखा से 45 हजार रूपये निकाल कर दुकान के लिए निकला।

इसी बीच दो अनजान युवक उसकी जेब से 45 हजार चुराकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सलाबतपुरा थाने में दोनों चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की।

नए साल के दौरान : गाड़ी चलाते शराबियों को पकडों, 100 रुपए का इनाम पाओ

गुजरात पुलिस को आदेश

सूरत (ईएमएस)। देशभर में नए साल के जशन की तैयारी हो रही है। इन जश्न के दौरान हुड़दंग काटने वालों पर लगाम लगाने के लिए गुजरात पुलिस ने प्लान बनाया है, जिसके तहत जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शख्स को पकड़ने पर पुलिसवालों को इनाम मिलेगा। शराब पीकर गाड़ी चल रहे हर एक शख्स को पकड़ने पर पुलिसवाले को 100 रुपए दिए जाएंगे। यह ऑर्डर दक्षणि गुजरात के आईजी जीएस मलिक ने दिया है।मलिक का यह आदेश सूरत,तापी,नवसारी,वलसाड और डांग जिलों के सुप्रीटेंडेंट्स के लिए है। गुजरात में यह सब नया नहीं है,वहां हर बार नए साल के जश्न पर नजर रखने के लिए खास तैयारियां की जाती हैं। राज्य में वैसे भी शराब पर रोक है,इसके साथ ही इससे नशे की वजह से होने वाले हादसों में भी कमी आती है। 31 दिसंबर 2016 को वलसाड पुलिस ने 325 लोगों को शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा था,उनमें से ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से गुजरात की सीमा में घुस रहे थे।

दमन-दीव से आते हैं पीकर:दक्षणि गुजरात के ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए दमन-दीव का रुख करते हैं और रात में ही अपने घर के लिए वापस हो आते हैं। गुजरात में शराबबंदी की वजह से लोग दमन-दीव से पीकर आते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया जाता है। वहां सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ा जाता है।एक अखबार से बात करते हुए आईजी मलिक ने बताया कि हम नए साल के दौरान शराब पर रोक के नियम का ध्यान रखते हैं,100 रुपए का इनाम भी पुलिसवालों को प्रोत्साहन देने के लिए रखा गया है। मलिक ने यह भी कहा कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है,इसलिए ज्यादातर लोग शराब पीकर गुजरात की सीमा में दाखिल होते हैं,इसतरह के लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।वहीं,वडसाड पुलिस के अधिकारी सुनील जोशी ने बताया कि सीमा के साथ-साथ इलाके के अंदर भी अच्छे से नजर रखी जा रही है।

साबरमती रिवरफ्रंट पर फ्लावर शो आज से, मुख्यमंत्री करेंगे उदघाटन

अहमदाबाद (ईएमएस)। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ३० दिसंबर की सुबह साढ़े नौ बजे अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से आयोजित फ्लावर शो-२०१८ का उद्घाटन करेंगे। यह फ्लावर शो आगामी ९ जनवरी-२०१८ तक सुबह १० से रात्रि ९ बजे के दौरान आम जनता के लिए साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट ग्राउंड, टैगोर हॉल के पीछे खुला रहेगा। वर्ष २०१३ से आयोजित हो रहे अहमदाबाद फ्लावर शो की इस छठी श्रृंखला में १ लाख वर्गमीटर के विशाल क्षेत्र में रंग-बिरंगे-खूश्बुदार फूलों की छटा बिखरी नजर आएगी।

प्रति वर्ष आयोजित होने वाले फ्लावर शो में मुख्यत: देश-विदेश के विविध किस्मों के फूलों के रोपों तथा फूलों से बने विभिन्न प्राणियों एवं पक्षियों सहित स्थापत्यों के स्कल्पचर का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा, देश के अन्य राज्यों की प्रसिद्ध नर्सरियों, जीवाणुनाशक दवा, बीज, खाद एवं गार्डन के औजारों की बिक्री के स्टॉल भी यहां लगाए जाते हैं। यहां आने वाले दर्शक बड़े पैमाने पर फूल-पौधों के अंकुर और दवाई, बीज, खाद तथा औजारों की खरीदी करते हैं। उद्घाटन समारोह में राजस्व मंत्री कौशिकभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, महापौर गौतमभाई शाह तथा महानगर के सांसद एवं विधायकगण उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि आर्किड, इंग्लिश गुलाब, कोर्नेशन तथा अन्य फूलों से बनाए गए जिराफ, तितली, हिरण, फ्लेमिंगो, मिकी माउस के अलावा अन्य प्राणी, सेल्फी वाल, ट्री, बॉल इत्यादि सहितकुल ५० से अधिक स्कल्पचर लाइव स्कल्पचर यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। बच्चों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए फ्लावर शो थीम आधारित लाइव चित्रकला स्पर्धा का आयोजन भी मनपा ने किया है।

ग्रीन हाउस का लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन, शहर तथा देश की प्रसिद्ध १४ नर्सरियों द्वारा विविध किस्मों के फूलों की प्रदर्शनी एवं बिक्री केन्द्र, खाद, बीज, जीवाणुनाशक दवाई, बगीचे के उपकरण तथा औजारों के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के ३२ बिक्री केन्द्र, हेरिटेज स्थलों की झांकी प्रस्तुत करने वाले स्टॉलों सहित १४ फूड स्टॉल तथा कला कारीगरी का नमूना पेश करती हस्तनिर्मित चीजों के १२० स्टॉल इस फ्लावर शो के आकर्षण का केन्द्र बनेंगे। फ्लावर शो जाने के लिए मनपा ने शहरीजनों के लिए बस सुविधा की व्यवस्था की है।

नौकरी की लालच देकर लाखों ठगनेवाला 12 साल बाद गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस)। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने की लालच देकर कई लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले शख्स को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पालडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के पालडी क्षेत्र में बतौर पीजी रहनेवाला महेश सुंदरजी धोकाई 12 साल पहले पोरबंदर में रहता था। वर्ष 2005 में पोरबंदर में ओफीस शुरू कर महेश नौकरीवांच्छुओं को सऊदी अरब समेत दुबई भेजने का काम करता था। महेश ने दुबई अल अरब कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने वालों की जरूरत होने का विज्ञापन दिया था। विज्ञापन देख कई लोगों ने महेश धोकाई से संपर्क किया। महेश ने इन लोगों से विजा समेत अन्य प्रोसिजर के लिए हजारों रुपए लिए थे। जिसमें मुकेश मकवाणा से रु. 41000, खीमजीभाई वाला से रु. 35000, चिमनभाई परमार से रु. 41000, प्रेमजीभाई कटारिया से रु. 40000, मालदेभाई से रु. 25000 और जीवन बाबूभाई से रु. 20000 समेत कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। जिसके बाद महेश पोरबंदर में ऑफीस बंद कर फरार हो गया था। इस बारे में उस वक्त पोरबंदर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके बाद से महेश धोकाई वान्टेड था। पिछले 12 सालों से फरार महेश धोकाई अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व सूचना के आधार पर शहर के पालडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

राजधानी एक्सप्रेस से कुचलकर माता-पुत्री की मौत

वलसाड (ईएमएस)। जिले के वापी में पुराने रेलवे क्रोसिंग के निकट राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से माता और पुत्री की मौत हो गई। जबकि अन्य दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वलसाड जिले की वापी के डुंगरा भोपालीनगर निवासी रेहाना शकीलखान अपनी पुत्री नाजिया ताहिर और साजिया व 6 महीने की बच्ची के साथ वापी के झंडा चौक स्थित मंडी में सब्जी खरीदने गई थी।

विजय मांगूकिया ने बोटाद की चिंतन शिबिर को बताया संभोग शिविर

अहमदाबाद (ईएमएस)। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति से जुड़े सूरत के एक पटेल युवक विजय मांगूकिया ने बोटाद में कल होनेवाली पास की चिंतन शिबिर को संभोग शिबिर बताते हुए पास नेता हार्दिक पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हार्दिक पटेल के करीबी रहे दिनेश बांभणिया ने आंदोलन के दौरान मारे गए युवकों के लिए एकत्र फंड का दुरुपयोग करने हार्दिक पटेल पर आरोप लगाया है।

पास छोड़कर भाजपा से जुड़े सूरत के विजय मांगूकिया ने कहा कि बोटाद में 30 दिसंबर को होनेवाली चिंतन शिबिर में कन्वीनर नहीं बल्कि कांग्रेस एजन्टों की नियुक्ति की जाएगी। आरक्षण आंदोलन का प्रणेता ने गुजरात और पाटीदारों की अस्मिता खरीदने का चेहरा बन चुका है। बोटाद में कल पास की चिंतन शिबिर नहीं बल्कि संभोग शिबिर होगी। क्योंकि अतीत में जो सेक्स सीडी सामने आई हैं और आनेवाले दिनों में भी सीडी आनेवाली है, जिससे कहा जा सकता है कि हवसखोर टोली पाटीदार समाज को कांग्रेस का एजंट बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल से पाटीदार आंदोलन में सक्रिय रहकर आरक्षण की मांग कर रहा था और मार भी खाई है। लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाकर कांग्रेस का एजन्ट बनाने का प्रयास के जाने के बाद हम पास से विमुख हो गए। उन्होंने कहा कि केशूबापा की आड में हवसखोर हार्दिक पटेल समाज को गुमराह कर रहा है। समाज के बुजूर्गों को भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार कानूनी रूप से पाटीदारों को आरक्षण मिलेगा। क्योंकि हार्दिक पटेल जोड़ तोड़ और तोड़ फोड की बात कर गुजरात के युवाओं को गुमराह कर रह है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, एवं 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास, सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com